

मुनाफे पर संकट, नई रणनीति बुनने लगीं कंपनियां



शाइन जैकब
चैन्सई, 31 जुलाई

अपर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने का सभाना का असर दिखा शुरू हो गया है, जिससे भारतीय कंपनियों के मुनाफे पर खत्म मंडरा रहा है। तिरपुर-जैसे हब में कंपनियां नियांतकों का कहना है कि अमेरिका पहले ही 10 प्रतिशत तक की छूट की मांग कर रहा है और भारतीय नियांतकों से वह शुल्कों के कारण पड़ने वाले वित्तीय बढ़ा का कुछ हिस्सा वहन करने का आग्रह कर रहा है।

ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय नियांतकों को बड़ी मात्रा में जाने वाले सामान्य उत्पादों पर औसतन 5 प्रतिशत तक का ही मुनाफा मिलता है। फैसला उत्पादों पर यह लगभग 20 प्रतिशत होता है। भारत से वॉलमार्ट, टारपट, एयेजन्स, कॉर्टको, मेसीज़, गैप और कॉलेजिया स्पॉटीवर्स, जैसे अमेरिकी ब्रांड सामान मांगते हैं। टैरिक की मार ऐसे समय पड़ी है जब इस साल जनवरी से मई के बीच अमेरिकी बाजार में भारतीय परिधानों की अयात हिस्सेदारी एवं दर्ज की गई है, जो इससे पिछले वर्ष इसी अवधि में 6 प्रतिशत पर थी। बाहर एंटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और एसएनक्यूएस इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक इलामोन विश्वनाथन ने कहा, 'कुछ ब्रांडों ने पहले से ही 10 प्रतिशत तक की छूट मांगनी रुख उत्पादों पर हमारा औसत मार्जिन केवल 5 प्रतिशत के आसपास है, जिससे यह मांग अव्यवहार्य हो जाती है।' उन्होंने यह भी कहा, 'भारत के पास वैसे भी आज नियात में 10 प्रतिशत से अधिक की छूट की क्षमता नहीं है। वह अभी क्षमता निर्माण की प्रक्रिया में है।' किसी अन्य देश के मुकाबले ट्रिनें और चेहरीदार पहले माल लेना चाहिए, जिन्होंने हर हाल में भारत से अधिक माल लेने का फैसला किया है।'

शुल्क की चिंता से नए नियांते स्तर पर रुपया

पृष्ठ 1 का शेष

सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक के एक डॉलर ने कहा, 'आयातकों और विदेशी पोर्टफोलियो नियेशों द्वारा डॉलर की खरीद की वजह से रुपये में नरमी आई है।' उन्होंने कहा, 'भारतीय रिझर्व बैंक ने 87.75 प्रति डॉलर पर हस्तक्षेप किया। रुपये में आगे भी नरमी बढ़ी रह सकती है और निकट अवधि में 87.90 प्रति डॉलर से अधिक रुपये देखा जा सकता है।'

बिज़नेस स्टैंडर्ड के सर्वेक्षण के अनुसार रुपये में भारी उठापटक रहने की उम्मीद है। सर्वेक्षण में शामिल ज्यादातर प्रतिपादियों ने कहा कि सिर्वर तक रुपया 88 प्रति डॉलर के करीब पहुंच सकता है।

व्यापार तनाव उभरे बाजार को मुराओं पर दबाव डालना जारी रखेगा, जिससे रुपया नए नियांते स्तर की ओर बढ़ रहा है और निकट अवधि में इसमें गिरावट बनी रह सकती है। हालांकि दिसंबर के अंत तक डॉलर के मुकाबले रुपये में सुधार होने की उम्मीद है।

आईआईआईआई बैंक में इकनोमिक्स रिसर्च के प्रमुख समीर नारंग ने कहा, 'भारत पर जो शुल्क वर्ष में आयाती है तो उसका असर पड़ा है। रुपया अन्य देशों की तुलना में भारत पर लगाए गए औरेशाकूर अधिक शुल्क पर प्रतिक्रिया देता है।' इस महीने रुपये में करीब 2.3 फीसदी की गिरावट आई है। दूसरी ओर डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है। इन रुपयों को देखते हुए हमारा मानना है कि अधिकांश मुद्राओं पर दबाव बना रहेगा। फिलालौल मध्यम अवधि का दृष्टिकोण इस बात पर निर्भर करेगा कि शुल्क का मुद्दा कैसे आगे बढ़ता है।

इस बीच अमेरिकी फेडल रिजर्व ने 9-2 के बोट से व्यापार दरों को 4.25 से 4.5 फीसदी पर खिंचा, जिसमें दूसरे दो गवर्नरों ने दर में कटौती के पक्ष में असहमति जताई। इस फैसले से गुवाहार को बाजार में उत्तरापटक देखी गई और डॉलर मजबूत हुआ तथा अमेरिकी ट्रेजरी की यील्ड बढ़ गई। चालू वित्त वर्ष में डॉलर के मुकाबले रुपये 2.4 फीसदी नीचे आया है। कुछ प्रतिभागियों का मानना था कि शुल्क से संबंधित घटनाक्रम के कारण निकट अवधि में रुपये पर और दबाव बढ़ सकता है लेकिन बाद में इसमें सुधार होने की उम्मीद है। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा, 'मुझे सिंतंबर तक और गिरावट की उम्मीद है। लेकिन इसके बाद सुधार होगा।' दिसंबर अंत रुपया 87 और 88 प्रति डॉलर के बीच कागजावार कर सकता है।'

रुपये पर सर्वेक्षण

बैंक	सिंतंबर अंत	दिसंबर अंत
आईआईआईआई बैंक	87\$/1-88.50/\$1	x
आईआईएफसी फर्स्ट बैंक	88/\$1	87/\$1
कर्सर वैश्य बैंक	86.80/\$1- 87.00/\$1	86.20/\$1- 86.50/\$1
क्रिसिल एक्स	x	87.50/\$1
सीआर फॉरेक्स	86.20/\$1-88.50/\$1	85.50/\$1-90/\$1
शिनहान बैंक	86.20/\$1-88.70/\$1	85.60/\$1- 87.95/\$1
बैंक ऑफ बड़ौदा	86.50/\$1- 87/\$1	87/\$1-88/\$1
एचडीएफी बैंक	87.00/\$1-88.00/\$1	86/\$1-87/\$1
मेकलाई फाइनैशियल सर्वे	86.50/\$1	88.00/\$1
फिनरेक्स द्वेरा एडवाइजर	86.80/\$1	87.80/\$1

जीडीपी में गिरावट संभव: बार्कलेज

वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी बार्कलेज ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका की तरफ से भारत पर 25 प्रतिशत सीमा शुल्क और जुमाना लगाए जाने से चालू वित्त वर्ष में देश की सकल शुल्क दर (जीडीपी) की वृद्धि दर में 0.30 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है।

बार्कलेज ने कहा, 'भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षाकृत बंद प्रकृति और घेरेलू मांग पर आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस शुल्क वृद्धि का व्यापक असर पड़ने की आशंका नहीं है।'

बार्कलेज के मुताबिक, यह शुल्क वृद्धि 1 अगस्त से लगाए जाने से वह शुल्क दर में 0.30 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है।

बार्कलेज ने कहा, 'भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षाकृत बंद प्रकृति और घेरेलू मांग पर आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस शुल्क वृद्धि का व्यापक असर पड़ने की आशंका नहीं है।'

बार्कलेज के मुताबिक, यह शुल्क वृद्धि 1 अगस्त से लगाए जाने से वह शुल्क दर में 0.30 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है।

बार्कलेज ने कहा, 'भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षाकृत बंद प्रकृति और घेरेलू मांग पर आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस शुल्क वृद्धि का व्यापक असर पड़ने की आशंका नहीं है।'

बार्कलेज के मुताबिक, यह शुल्क वृद्धि 1 अगस्त से लगाए जाने से वह शुल्क दर में 0.30 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है।

बार्कलेज ने कहा, 'भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षाकृत बंद प्रकृति और घेरेलू मांग पर आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस शुल्क वृद्धि का व्यापक असर पड़ने की आशंका नहीं है।'

बार्कलेज के मुताबिक, यह शुल्क वृद्धि 1 अगस्त से लगाए जाने से वह शुल्क दर में 0.30 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है।

बार्कलेज ने कहा, 'भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षाकृत बंद प्रकृति और घेरेलू मांग पर आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस शुल्क वृद्धि का व्यापक असर पड़ने की आशंका नहीं है।'

बार्कलेज के मुताबिक, यह शुल्क वृद्धि 1 अगस्त से लगाए जाने से वह शुल्क दर में 0.30 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है।

बार्कलेज ने कहा, 'भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षाकृत बंद प्रकृति और घेरेलू मांग पर आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस शुल्क वृद्धि का व्यापक असर पड़ने की आशंका नहीं है।'

बार्कलेज के मुताबिक, यह शुल्क वृद्धि 1 अगस्त से लगाए जाने से वह शुल्क दर में 0.30 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है।

बार्कलेज ने कहा, 'भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षाकृत बंद प्रकृति और घेरेलू मांग पर आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस शुल्क वृद्धि का व्यापक असर पड़ने की आशंका नहीं है।'

बार्कलेज के मुताबिक, यह शुल्क वृद्धि 1 अगस्त से लगाए जाने से वह शुल्क दर में 0.30 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है।

बार्कलेज ने कहा, 'भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षाकृत बंद प्रकृति और घेरेलू मांग पर आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस शुल्क वृद्धि का व्यापक असर पड़ने की आशंका नहीं है।'

बार्कलेज के मुताबिक, यह शुल्क वृद्धि 1 अगस्त से लगाए जाने से वह शुल्क दर में 0.30 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है।

बार्कलेज ने कहा, 'भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षाकृत बंद प्रकृति और घेरेलू मांग पर आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस शुल्क वृद्धि का व्यापक असर पड़ने की आशंका नहीं है।'

बार्कलेज के मुताबिक, यह